छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विवेक कुमार शर्मा[1] डॉ. तपेशचन्द्र गुप्ता[2]

1. शोध छात्र/सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर

2. शोध निर्देशक/प्राध्यापक (वाणिज्य) शास जे. वाय. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर

सारांश

आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। मानव जीवन में कुछ बुनियादी सुविधाओं में से आवास एक प्रमुख संसाधन है जो उसके जीवन स्तर के मूल्यांकन का पैमाना होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरीकरण के विस्तार से आकर्षित होकर ग्रामीण गांव से नगर की ओर आकर्षित हुए है, फिर भी नगरों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है तथा आवास की आवष्यकता एवं आधारभूत सुविधाओं की कमी ग्रामीणों को शहर की ओर आकर्षित करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपरोक्त योजना की सकारात्मक भूमिका पायी गयी है तथा ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध हो।

प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार 2,55,40,196 है। जिसमें से 76.76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अतः राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक है, ग्रामीण विकास बुनियादी सुविधाओं जैसे आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, विद्युतीकरण, रोजगार या स्वरोजगार के अवसर, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि आधारिकत उद्योग के विकास पर निर्भर है। अतः विकास की उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में आवास की समस्या को दूर करने के लिए अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 25 वर्ग मीटर में एक कमरा, रसोईघर, बरामदा व शौचालय सहित पक्के मकानों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2016–17 से सामान्य जिलों के लिए 1.20 लाख रू एवं आई.ए.पी. जिलों के लिए 1.30 लाख प्रति आवास इकाई लागत निर्धारित की गई है। आवास में शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा से 12,000 रू. की राशि प्रति आवास दिया जा रहा है। गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 कार्य दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। योजनांतर्गत वर्तमान में 174 रू. प्रति दिवस मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) द्वारा ग्रामीण परिवार को सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराने के साथ–साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आवास व बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का अध्ययन।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में योगदान का अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पना :–

H_1 छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सुविधायुक्त आवास की आवश्यकता अधिक है।

H_2 छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आवास की कमी को दूर करने में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनगणना 2011 तथा आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018–19 छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त द्वितीयक समंकों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में आवश्यकतानुसार एकत्रित तथ्यों को मुख्य सारणियों में प्रस्तुत किया गया है व सारणियों के अनुसार आलेखों का निर्माण किया गया है।

प्राप्त जानकारी व विश्लेषण :–

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आवास की आवश्यकता का अध्ययन के लिए ग्रामीण जनसंख्या का विश्लेषण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का विवरण निम्नांकित तालिका अनुसार है :–

तालिका कमांक – 1

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की स्थिति (1952 – 2011)

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
कुल जनसंख्या वृद्धिदर (%)	–	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर (%)	–	18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
शहरी जनसंख्या (लाख में)	3.64	7.63	12.08	20.58	30.65	41.86	59.37
शहरी जनसंख्या में वृद्धिदर (%)	–	109.52	58.37	70.39	48.9	36.58	41.84

स्त्रोत :– आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनायन छत्तीसगढ़ पृष्ठ 193, 202

रेखाचित्र कमांक 01

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर (%) 1951 से 2011 तक

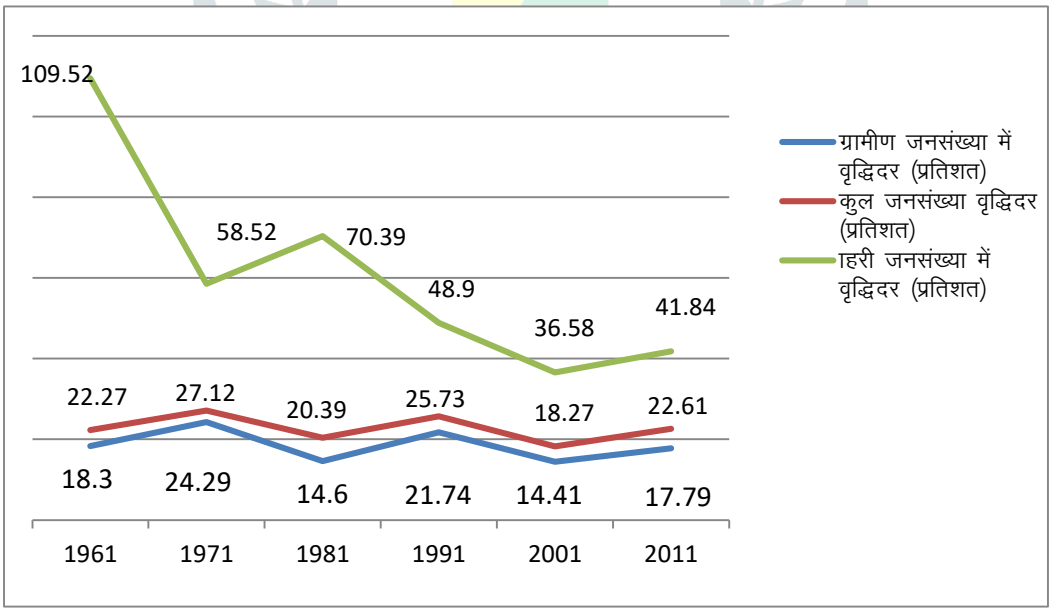

रेखाचित्र कमांक 02

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का वितरण 1951 से 2011 तक

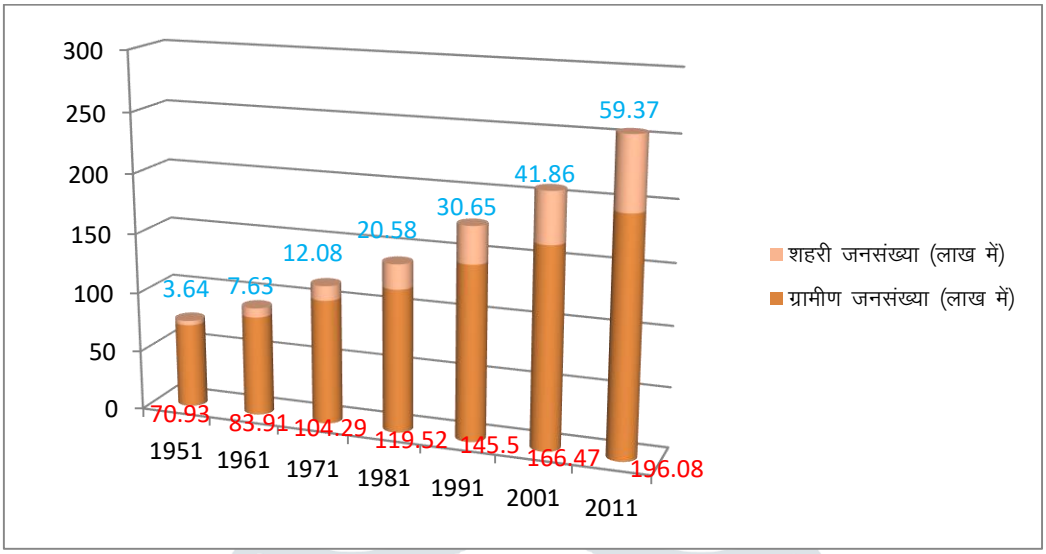

उपयुक्त तालिका व रेखाचित्र से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में विगत पांच दशकों में समग्र राज्य की जनसंख्या वृद्धिदर की तुलना में ग्रामीण वृद्धिदर में कमी पायी गयी है, और नगरीय जनसंख्या वृद्धिदर में तेजी पायी गयी है परन्तु इसके बाद भी नगरीय जनसंख्या के तुलना में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार 76.76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में व 23.24 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करती है।

परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता जो एक साथ रहते है। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवारों के मकानों की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका कमांक – 2

छत्तीसगढ़ में परिवारों के मकानों की स्थिति जनगणना 2011 के अनुसार

मकान सूची मद	ग्रामीण	प्रतिशत	नगरीय	प्रतिशत	कुल
अच्छी	1,822,189	69.6	7,95,705	30.4	2,617,894
रहने योग्य	2,373,707	78	4,10,350	22	2,784,057
जीर्ण–शीर्ण	1,88,216	85.2	32,683	14.8	2,20,899
कुल	4,384,112	80	1,238,738	20	5,622,850

स्त्रोत :– भारत की जनगणना 2011 छत्तीसगढ़ श्रृंखला पृष्ठ (ix)

रेखाचित्र कमांक 03

छत्तीसगढ़ में मकानों की स्थिति

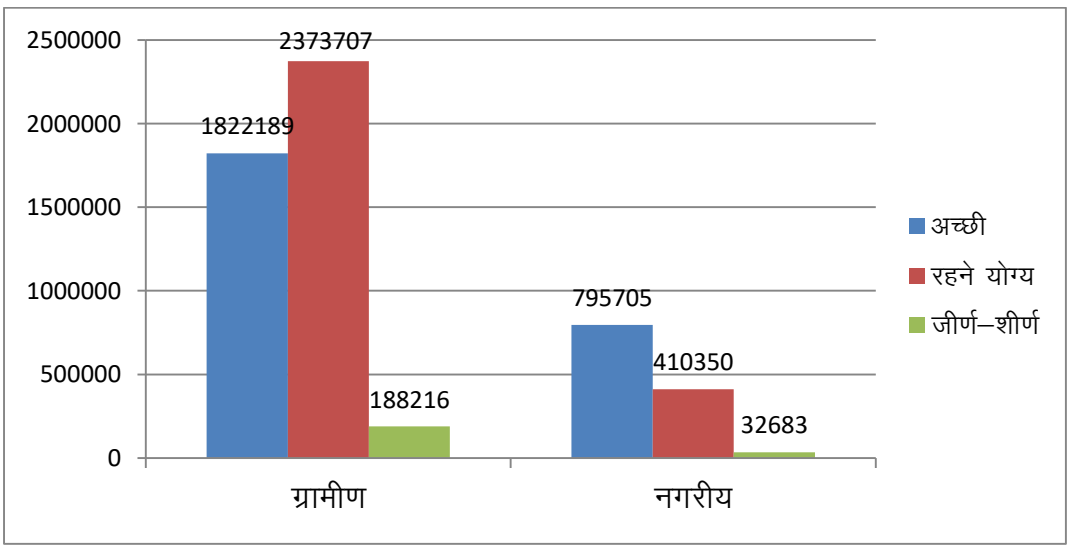

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 5,624,850 परिवार निवार करते हैं, इसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 4,384,112 परिवार ग्रामीण व 1,238,738 परिवार अर्थात् 20 % नगरीय क्षेत्र में निवास करते है। कुल 2,20,899 जीर्ण–शीर्ण मकान है, जिसमें 85.2 प्रतिशत अर्थात् 1,88,216 ग्रामीण क्षेत्र में और 14.8 प्रतिशत अर्थात् 32,683 नगरीय क्षेत्र में हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अप्रैल 2016 से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र बने आवास का विवरण निम्नांकित तालिका अनुसार हैं :–

तालिका कमांक – 03

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का विवरण (2017–18 व 2018–19)

वर्ष	लागत (लाख में)	आवास (पूर्ण/निर्माणधीन)
2017–18	2,98,076.60	**1,31,195 पूर्ण 74, 914, निर्माणाधीन**
2018–19 (सितबंर तक)	1,70,695.59	**9,399 पूर्ण 2,95,411 निर्माणाधीन**
कुल		**1,40,594 पूर्ण 2,95,411 निर्माणाधीन**

स्त्रोत :– आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018–19 आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचानालय छत्तीसगढ़, पृष्ठ 202

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1,40,594 आवास का निर्माण हो चुका है, व 2,95,411 आवास निर्माणधीन है, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पूर्ण/निर्माणधीन आवास संख्या 4,36,005 है।

निष्कर्ष :–

H_1 :– शोध अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के पास सुविधा युक्त आवास की कमी है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में सुविधायुक्त आवास की आवश्यकता अधिक है। **शोध परिकल्पना स्थापित।**

H_2 :– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य में सफल रहा है। अतः शोध अध्ययन पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आवास की कमी को दूर करने में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। **शोध परिकल्पना स्थापित।**

सुझाव :–

उपरोक्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अपने उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। योजना में स्वच्छता, जलसंग्रह, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए। हरियाली छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की पहचान है, अतः सभी योजनाओं का आधार पर्यावरण पोषित विकास होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. समग्र छत्तीसगढ़ 2018 – माधव हरदेवी– छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी
2. भारत की जनगणना 2011, मकानों, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं तथा परिसम्पत्ति संबंधित सारणियां छत्तीसगढ़ श्रृंखला 23
3. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018–19 आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन
4. मुखर्जी रविन्द्रनाथ, 2007, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाषन
5. आवास एवं बुनियादी सुविधाओं का प्रचलन एवं असमानताएं, 2001, हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेषन लिमिटेड